[Shri Mehr Chand Khanna]

from the General Secretary, All Tripura Refugee Association, Agartala. According to this telegram, about hundred refugees had started hunger strike from 2nd March. On the same day, I also received a letter from Shri Biren Dutt in this connection. As we had no information about the reported hunger-strike, the Tripura Government were asked to intimate the facts.

The total number of new migrants who have come to Tripura during the months of January and February 1956, was 2,397 and 5,342 respectively as against the average monthly arrival of about 1,400 persons during the last year. For the migrants arriving through the Agartala check post, a reception centre has been opened at the border. For those arriving through Dharmanagar, Kailasahar, Kamalpur, Khoai, Belonia, and Sabroom, arrangements have been made for the grant of cash doles.

As regards the old migrants, most of them are living with friends and relations and some are in camps and getting cash doles. 6,900 families have applied for loans and their applications are being inquired into. I personally visited Tripura on the 18th, 19th and 20th January 1956 and saw for myself the condition of the displaced persons and the progress of the various rehabilitation schemes. I met the displaced persons and their representative organisations and discussed their difficulties. Appropriate action is being taken on the various proposals which emanated after my discussions. The Central Tractor Organisation has carried out a survey and it is proposed to reclaim a large tract of land in Raima Serma Valley. The proposal is under examination. Some schemes for the setting up of cottage and small scale industries are also under consideration.

On the 2nd March, a few displaced persons of Nihal Chandra Nagar placed themselves in front of the gate of the Rehabilitation Directorate and made a number of demands. The number of displaced persons gradually increased to about a hundred and by the 6th instant, they adopted a more truculent attitude and started obstructing the staff from entering the office by the main gate. Efforts were made to persuade them to call off the picketing. The Chief Commissioner considered the situation fully. He impressed upon the displaced persons that picketing and obstruction of Government servants carrying out their normal duties could not be tolerated. He also told them that their demands would be duly considered. The displaced persons thereupon abandoned the picketing and dispersed at 2.30 P. M. on the 7th March.

Of the demands, two are of an important nature, *i.e.* one relating to the definition of a displaced person and the other regarding the grant of loans at West Bengal rates. The definition of a displaced person has recently been revised in consultation with the Rehabilitation Ministers of the Eastern States. It is not our intention to liberalise it any further. In regard to the grant of loans, though certain ceilings have been fixed, the amount of loan is given according to the requirements of displaced persons. Loans are co-related with the rehabilitation needs. This is essential to avoid wastage of public funds.

In conclusion, I would like to assure this House that every possible effort is being made in the matter of relief and rehabilitation of displaced persons from East Pakistan, including those who have come to Tripura. The problem has, however, become more difficult and complex on account of the continuous and increased migration from East Pakistan.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 2 BILL

The Minister of Railways and Transport (Shri L. B. Shastri): I beg to move: *

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1955-56 for the purposes of Railways, be taken into consideration".

Mr. Speaker: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1955-56 for the purposes of Railways, be taken into consideration".

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

---

*Moved with the recommendations of the President.

Shri L. B. Shastri: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

GENERAL BUDGET— GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

Mr. Speaker: The General Discussion on the General Budget will now be resumed. The time allotted is twenty hours. The time taken is 5 hours 54 minutes and the balance is 14 hours and six minutes.

सेठ गोविन्द दास (मंडला जबलपुर—दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं वित्त मंत्री जी को उन के इतने सुन्दर बजट पर बधाई देना चाहता हूं। यह बजट यथार्थ में एक विशेषज्ञ का बजट है और थोड़े ही समय में इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण भी मिले हैं। यह बजट भारतवर्ष की मजबूत आर्थिक परिस्थिति का द्योतक है। कर वृद्धि के सम्बन्ध में भी, इस प्रकार की कर वृद्धि नहीं हुई है जिस से सामान्य जनता का बोझ बढ़ा हो और इन थोड़ दिनों में देश के बाजारों की जो स्थिति रही वह इसे प्रमाणित करता है कि समूचे देश में इस बजट का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है।

स्वतंत्र देश के सभी बजट महत्त्वपूर्ण होते हैं। हमारी स्वतंत्रता के पश्चात् जितने बजट इस सदन में आये उन सब का आपना आपना महत्त्व था। परन्तु इस बजट का विशेष महत्त्व इस लिये है कि हमारी जो दूसरी पंच वर्षीय योजना आरम्भ होने वाली है उस योजना का यह पहला बजट है। स्वतंत्र होने के पश्चात् हम उन्नति क पथ पर ठीक तरह से अग्रसर हो रहे हैं। हम ने अनेक राजनैतिक महत्त्व के कार्य कर डाले। स्वतंत्र होते के पश्चात् सब से पहले स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ६०० रियासतों के प्रश्न को हल कर हमारे देश में राजनैतिक एकता की स्थापना की। उस के बाद हम ने अपना संविधान बनाया, आम चुनाव हुए बालिग मताधिकार पर, और संसार के अब तक के इतिहास में हम सब से बड़े प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनैतिक महत्त्व की बातों को करने के उपरान्त अब हम आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और इस विषय में हमारा स्पष्ट लक्ष्य है समाजवादी सामाजिक रचना। यदि हम उन देशों को भी देखें जो कि साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार चलते हैं तो भी हमें मालूम होना चाहिये कि भिन्न भिन्न देशों की साम्यवादी रचना उन देशों की परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की है। हम अपने देश में एक विशेष प्रकार की समाजवादी रचना की स्थापना करना चाहते हैं जो समाजवादी रचना हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हो।

पहली योजना में हमने योजना बनाकर कार्य करना आरम्भ किया था। उस समय हमें न तो योजना बनाकर काम करने का अनुभव था और न हम ने उसके पहले कोई समाजवादी योजना की घोषणा की थी। हमारी पहली पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बहुत बड़ा अन्तर है। पहला अन्तर तो यह है कि यह दूसरी योजना समाजवादी समाज की रचना को ध्यान में रख कर बनी है। दूसरे यह पहली योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी है और तीसरा अन्तर यह है कि यह योजना एक लचीली योजना है। हम हर वर्ष अपने कार्य का अनुभव प्राप्त करते जायेंगे और जैसी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनके अनुसार द्वितीय योजना पंच वर्षीय होते हुए भी हर वर्ष उस में परिवर्तन भी होते जायेंगे। इस सम्बन्ध में जो कल श्री अशोक मेहता ने एक बात कही थी उसको मैं इस देश के लिए एक अभिशाप मानता हूं। उन्होंने कहा था कि योजनाबद्ध कार्य करने के लिए हम को कंट्रोल्ज (नियन्त्रण) की आवश्यकता होगी। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि योजनाबद्ध कार्य भी हर देश की परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं और कंट्रोल्ज का हम को जो अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं वित्त मंत्री जी से जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस अभिशाप को वे फिर से इस देश पर लागू न करें। कीमतों का कंट्रोल मेरी समझ में आता है लेकिन वस्तुओं के कंट्रोल का जो नतीजा इस देश में निकला था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश में फैला था, उन सब बातों को देखते हुए चाहे कंट्रोल साम्यवादी और समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार भी क्यों न हों, उनको लागू करना मैं उचित नहीं मानता। सिद्धान्त मानवों के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, मानव और देश सिद्धान्तों के लिए नहीं होते। इस लिये जितना भी मुझ में बल है, उस सारे बल के साथ में कहना चाहता हूं कि श्री अशोक